बढ़ते बीहड़ और वीरान होते गांव

प्रमोद भार्गव

कभी खूंखार दस्युओं के अभयारण्य रहे चंबल के बीहड़ आज तेज़ रफ्तार से बढ़ते हुए, भिंड व मुरैना ज़िलों के 200 गांवों के वजूद के लिए खतरा बन गए हैं। इन गांवों की 52 हज़ार हैक्टर कृषि भूमि लगातार बीहड़ों में तब्दील होती जा रही है। इसे रोकने व बीहड़ों के सफाए के लिए मध्यप्रदेश सरकार विश्व बैंक और भारत सरकार की मदद से अरबों रूपए खर्च कर चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक शून्य रहा है।

पूरे देश में 33 करोड़ हैक्टर भूमि है, जिसमें से 13 करोड़ हैक्टर नितांत बंजर है। इसी बंजर भूमि में चंबल के अभिशप्त बीहड़ शामिल हैं। चंबल संभाग अर्थात मुरैना और भिण्ड ज़िलों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 16.14 लाख हैक्टर है, जिसमें से 7 लाख हैक्टर क्षेत्र चंबल और उसकी सहायक नदी कुंवारी के दुर्गम व उबड़-खाबड़ बीहड़ों का है। ये बीहड़ अपनी भौगोलिक स्थिति स्थिर रखते तो चिंता की कोई बात न थी।

देश की लगभग 8 हज़ार हैक्टर भूमि हर साल बीहड़ बनती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक बीहड़ों में सालाना 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। अकेले भिंड और मुरैना ज़िलों में ही पिछले 30 साल के भीतर बीहड़ों में 60 फीसदी इजाफा हुआ है। 1943 और 1950 के बीच इन दो ज़िलों में सालाना 800 हैक्टर बीहड़ों की वृद्धि हुई थी। 1950 और 1975 के बीच यह औसत बढ़कर 5 हज़ार हैक्टर सालाना हो गया। चंबल संभाग में इस समय प्रति व्यक्ति करीब 0.33 हैक्टर कृषि क्षेत्र है जो बीहड़ों के निरंतर फैलाव के कारण अगले 50 सालों में घटकर 0.124 हैक्टर प्रति व्यक्ति रह जाएगा। यदि यही हालात रहे तो कालांतर में चंबल व कुंवारी नदियों के बीहड़ का फैलाव परस्पर मिल जाएगा और तब दोनों नदियों के बीच स्थित कृषि भूमि पूरी तरह बीहड़ों में तब्दील हो जाएगी। बीहड़ों के फैलते जाने का मुख्य कारण जंगलों की बेतहाशा कटाई है। चंबल घाटी में बीहड़ों के इस विस्तार से दस फीसदी गांव पूरी तरह वीरान हो चुके हैं। भूमि और जल के असंतुलन व अनियंत्रण से उपजी यह समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है। सुधार-कार्यक्रम में यह जानने की कोशिश ही नहीं की गई कि बीहड़ बनते कैसे हैं।

इस अंचल के पर्यावरण को बचाने व अंधविश्वासों को दूर करने के प्रयासों में लगी संस्था 'साइंस सेंटर' ने अपने अध्ययनों में पाया है कि यदि ये बीहड़ इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आने वाले 50 सालों के भीतर भिंड और मुरैना जिलों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। संस्था ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर आगाह किया है कि बीहड़ों के विस्तार से बेरोजगार हुए किसानों के लगान और कर्ज माफ करने की कार्यवाही तुरंत शुरू की जाए। जिन किसानों की जमीन कटाव में आ गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा तो दिया ही जाए, उनके पुनर्स्थापन और पुर्नवास की नीति भी लागू की जाए।

पिछले 30 सालों के भीतर भिंड और मुरैना अंचल के करीब 1000 गांव बीहड़ों के लगातार विस्तार के कारण तबाह हो चुके हैं। आंचलिक बोली में बीहड़ों के इस फैलाव को 'बेचारगी' कहते है। इस 'बेचारगी' के चलते सैकड़ों गांव कई टुकड़ों में विभाजित होकर एक विचित्र भौगोलिक विपदा भोग रहे हैं। ऐसे गांवों में हालात इतने बदतर है कि इन गांवों तक पहुंचना ही दुर्गम व कष्टप्रद हो गया है। इस कारण ये गांव स्वास्थ्य, पेयजल और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों से भी निरन्तर वंचित होते जा रहे हैं।

इस समस्या के प्रति सरकार अभी भी पूरी तरह से संवेदनशील नहीं है। इसलिए वह अभी भी केवल मिट्टी के टीलों और टीलों के बीच बनी खाइयों को ही बीहड़ मानती रही है। जबकि इस इलाके में आने वाली बंजर

और पड़ती भूमि को भी बीहड़ क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए।

ऐसा नहीं है कि चंबल के बीहड़ों से जनता को निजात दिलाने की सरकार को चिंता न हो। प्रदेश सरकार विश्व बैंक व भारत सरकार की आर्थिक सहायता से बीहड़ों के समतलीकरण और इनके फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए एक लम्बी परियोजना चला चुकी है। इस बीहड़ उन्मूलन योजना के तहत भारी भरकम मशीनों से बीहड़ तोड़ने के उपक्रम किए गए हैं और बीहड़ों का फैलाव रोकने के लिए वायुयानों से वृक्षारोपण के लिए बीज बरसाए गए हैं। यह कार्यवाही पूरी तरह सरकारी स्तर पर हुई, नतीजतन बीहड़ उन्मूलन योजना हवाई रोमांच का आनंद लूटने तक सिमटकर रह गई।

बीहड़ों के उन्नयन के लिए 1919 में ग्वालियर रियासत ने भी एक आयोग गठित करके वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया था। 1949 में अमेरिकी विशेषज्ञ डॉ. हर्ट को बुलाकर भूमि संरक्षण पर विचार भी किया गया था। 1988-92 तक केन्द्र सरकार ने चंबल में दस्यु समस्या निराकरण के लिए बीहड़ों के समतलीकरण, सड़कों के निर्माण तथा वृक्षारोपण के लिए 363 लाख रूपए खर्च किए लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा।

दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के दौरान भी जनता को बीहड़ों के अभिशाप से मुक्ति दिलाने की चिंता की गई थी। तब यह काम केंद्र सरकार की मदद से पूर्व सैनिकों ने किया। यह एक मौलिक प्रयोग था। सरकार ने इस समस्या से जूझने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को भी न्यौता। बीहड़ों के उन्मूलन के पहले चरण में 1200 हैक्टर क्षेत्र के बीहड़ों का समतलीकरण करने का प्रस्ताव था। बीहड़ों को बढ़ने से रोकने व पानी के बहाव से भूमि के कटाव को रोकने के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण भी किया जाना था। इस योजना के पहले चरण में 1 करोड़ 30 लाख 80 हज़ार रूपए खर्च भी किए गए, लेकिन इसके भी परिणाम उम्मीदों के धरातल पर खरे नहीं बैठे।

दरअसल सबसे पहले बीहड़ों के फैलाव के कारणों की पड़ताल करनी चाहिए। इस क्षेत्र के जलवायु व पारिस्थितिकी अध्ययन की भी ज़रूरत थी। क्योंकि केवल पेड़ों का काटा जाना ही बीहड़ों के विस्तार का कारण नहीं है। वैसे भी जहां-जहां बीहड़ों के विकराल व घने समूह हैं, वहां नाम मात्र के जंगल रहे हैं। आखिर क्यों कुदरत भी यहां जंगल नहीं रोप पाई? इन कारणों की पड़ताल करनी चाहिए।

बीहड़ों के विस्तार में अवरोध पैदा करने के साथ-साथ ग्राम विकास की योजनाएं भी जारी रहनी चाहिए। तभी चंबल अंचल के लोग इन योजनाओं से जुड़ेंगे। बीहड़ क्षेत्र के गांवों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाने से व्यापार का विस्तार होगा। बीहड़ क्षेत्र में जो किसान ज़मीन चाहते हैं उन्हें बिना किसी विलंब के पट्टे दिए जाने चाहिए। इससे ये किसान खुद बीहड़ों के समतलीकरण और भूमि के कटाव को रोकने की दिशा में कदम उठाएंगे। इस अंचल की उपजाऊ भूमि नष्ट कर मालनपुर और बानमौर जैसे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बजाए बीहड़ क्षेत्र में ही नगरों का विकास किया जाना चाहिए। यदि बीहड़ों के विस्तार को रोकने के लिए वैज्ञानिक दूरदृष्टि से काम नहीं लिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब इस अंचल में इससे उपजी गरीबी शासन व प्रशासन के लिए नई समस्या खड़ी कर देगी। *(स्रोत फीचर्स)*